नाटो' के हमलों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका

2687. **श्री कलिप सिब्बल** :

श्री राज मोहिन्दर सिंह :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 'नाटो' देशों द्वारा हाल ही में यूगोस्लाविया पर किये गये हमले के संबंध में शांति स्थापित रखने में सन्तोषजनक भूमिका नहीं निभा पाई थी,

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया हैं

(ग) क्या सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ (यू एन ओ) के वर्तमान ढांचे और कार्यकरण में व्यापक सुधार लाने की आवश्यकता पर विचार किया गया हैं, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई हैं ?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद युगोस्लाविया संघीय गणराज्य के कोसोवो के स्वायत्तशासी प्रान्त में हो रही घटनाओं पर विचार कर रही थी । परिषद ने कोसोवो में इस स्थिति से निपटने के लिए तत्कालीन युगोस्लाविया से सम्बधिंत सम्पर्क दल को प्राधिकृत किया था । तथापि परिषद के विधिवत् अधिकार के बिना नाटों ने युगोस्लाविया संघीय गणराज्य पर आक्रमण शुरू कर दिए । सरकार इन घटनाओं पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और सरकार ने 24 और 25 मार्च, 1999 को अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की थी । हमारे वक्तव्यों में संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करने वाली किसी प्रकार की एकपक्षीय कार्रवाई अथवा ऐसी किसी अन्य कार्रवाई का साफ तौर पर विरोध किया गया हैं । इस एकपक्षीय कार्रवाई ने संयुक्त राष्ट्र की सम्पूर्ण प्रणाली के अधिकार को गम्भीर रूप से खोखला कर दिया हैं । हमने युगोस्लाविया संघीय गणराज्य की प्रभसम्पन्नता और क्षेत्रीय अखण्डता की संरचना के भीतर शांतिपूर्ण तरीकों से इस संकट के समाधान की मांग की हैं ।

(ग) और (घ) भारत स्थायी और गैर-स्थायी सदस्यों की श्रेणी में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार का समर्थन करता हैं । विस्तार और सुधार सामूहिक पैकेज का एक समेकित हिस्सा होना चाहिए । भारत सुरक्षा परिषद की पुनर्सरचना पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के खुले कार्यकारी दल की चर्चाओं में सक्रियता से हिस्सा ले रहा हैं ।

Advertisements in Pakistani Newspapers

2688. SHRI SATISHCHANDRA SITARAM PRADHAN: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Pakistani newspapers are publishing the advertisements to paralyse India;

(b) which are the people, organisations, press involved with this; and

(c) what is the reaction of the Pakistani Prime Minister in the present situation?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): (a) to (e) Government is aware of the hostile anti-India propaganda conducted in Pakistan. This activity, conducted through mass media, is totally contrary to the understanding set out in the Simla Agreement of 1972 that the two countries will refrain from hostile propaganda against each other. We have called on the Government of Pakistan to adhere to this understanding. This issue has also been taken up regularly in the composite bilateral dialogue.

Test firing of Agni-II missile

2689. SHRI SANJAY NIRUPAM: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether India under pressure of USA has withheld the test firing of Agni-II missile;

(b) if so, whether it is not against India's resolve to build and maintain a minimal deterrent for country's security; and

(c) for how long India will succumb under pressure and postpone test firing of Agni-II missile?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): (a) No Sir. A successful flight test of Agni-II was carried out on 11 April.

(b) and (c) Government is committed to maintaining a minimum credible nuclear deterrent. Government's decisions relating to our nuclear ;and missile programmes will continue to be taken in accordance with our own assessment of national security requirements.

All round development of tics between India and UK

2690. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government of U.K. has expressed a desire for all round development of ties between the two countries; and

(b) if so, Government's reaction thereon?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) Government has welcomed the expression of this desire which coincides with our own policy of working to develop a broad-based, mutually beneficial relationship with the UK.

विदेश मंत्री को अमरीका की यात्रा का नियंत्रण

2691. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या अमरीका ने भारत के माननीय विदेश मंत्री को अमरीका की यात्रा करने और अमरीका के विदेश मंत्री के साथ चर्चा करने के लिए निमंत्रण दिया हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने अपनी अमरीका यात्रा की तारीखें निर्धारित कर ली हैं,

(ग) क्या चर्चा केमसौदे, को उनके द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया हैं, और

(घ) यदि हां, तो भारत को सहायता देने और द्विपीक्षीय संबंधों के बारे में अमरीका का दृष्टिकोण क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह) : (क) और (ख) भारत जून, 1998 से अमरीका के साथ उच्च स्तरीय व्यापक वार्ता कर रहा हैं । विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंह और अमरीकी विदेश उपमंत्री श्री स्ट्रोब तालबोट को यह वार्ता करने के लिए नामित प्रतिनिधियों के रूप में नियुक्त किया गया हैं । इस वार्ता का पिछला दौर जनवरी, 1999 में नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ ।

इस वार्ता के अगले दौर के बारे में इस वर्ष के मध्य में विचार किया गया हैं जिसकी तारीख और स्थान दोनों पक्षों के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा ।

(ग) अब तक हुई बातचीत सुरक्षा, निरस्त्रीकरण और अप्रसार से संबंधित मसलों पर केन्द्रित रही । इस बातचीत को अब संकुचित किया गया हैं और चार मसलों अर्थात व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि एम एम सी टी, निर्यात नियंत्रण तथा रक्षा स्थिति पर केन्द्रित किया गया हैं ।

(घ) दोनों पक्षों में इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया हैं कि इस वार्ता का उद्देश्य सुरक्षा से सम्बद्ध मामलों पर एक-दूसरे के विचारों में तालमेल लाना तथा भारत और अमरीका के बीच व्यापक आधारित संबंधों की नीवं डालना हैं ।

अमरीकी सरकार ने 7 नवम्बर, 1998 को भारत के विरूद्ध कुछ आर्थि प्रतिबंधात्मक उपायों को उठाने की घोषणा की हैं । ये तीन अमरीकी संस्थाओं अर्थात् एक्जिम बैंक, ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन और व्यापक विकास प्राधिकरण के कार्यक्रमों से संबंधित हैं । अमरीकी सरकार ने वाणिज्यिक अमरीकी बैंकों तथा अन्तर्राष्ट्रीय सैन्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियाकलापों पर लगे प्रतिबंधों को भी उठा लिया हैं । बुनियादी आवश्यकता के क्षेत्रों में सहायता से सम्बद्ध द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं ।

अमरीकी सरकार ने कहा हैं कि वह भारत के साथ अपनी वार्ता में प्रगति को स्वीकार करते हुए यह उपाय कर रहा हैं ।

फरवरी, 1999 में अमरीका ने आन्ध प्रदेश राज्य में अवसंरचना तथा विद्युत विकास से सम्बद्ध विश्व बैंक के ऋण के अनुमोदन में बाधा नहीं पहुंचाई ।